10

10.1 निधियों के स्रोत
10.2 निधियों का उपयोग
10.3 आय और व्यय
10.4 कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश
10.5 प्रभाव और प्रगति के लिए रणनीतिक निवेश और संग्रहण
अध्याय 10 का अनुबंध: वित्तीय वर्ष 2024 में नाबार्ड की सहायक संस्थाओं का कार्यनिष्पादन

वित्त के माध्यम से विकास

31 मार्च 2024 को नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार, वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 13.6% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹9 लाख करोड़ से अधिक था. वर्ष की उच्चतम उपलब्धि यह थी कि यह पहला वर्ष था जब पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी सामाजिक बॉण्ड जारी किए गए (शोकेस 10.1).

शोकेस 10.1: नाबार्ड ने पहली बार सामाजिक बॉण्ड को जारी कर इतिहास रचा

'नाबार्ड ईएसजी निवेश की अवधारणा से पहले से है और अपनी स्थापना से ही भारत में ग्रामीण क्षेत्र के संधारणीय विकास पर केंद्रित है. अब, यह हम पर है कि हम भारतीय बाजारों को भारत की ग्रामीण जनता तक पहुंचाएं.'

—शाजी के वी अध्यक्ष, नाबार्ड.

नाबार्ड ने वर्ष के दौरान भारत के पहले रुपी-डिनॉमिनेटेड सामाजिक बॉण्ड जारी कर ईएसजी निवेश के कार्य का अग्रणी बन गया. इसका लिस्टिंग समारोह 29 सितंबर 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऐतिहासिक मार्केट हॉल में आयोजित किया गया. ₹1,000 करोड़ के बॉण्ड जारी करने से नाबार्ड, भारतीय घरेलू बाज़ार में सबसे बड़ा जारीकर्ता बन गया है. इतना उत्साह था कि बोलियों में ₹8,560 करोड़ के ऑफर प्राप्त हुए जिनमें से ₹1,040.5 करोड़ के ऑफर स्वीकार किए गए. इस एएए रेटेड बॉण्ड को अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ के सामाजिक बॉण्ड दिशानिर्देशों के तहत केपीएमजी द्वारा बाह्य रूप से प्रमाणित किया गया था.

इस पेशकश के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग तेलंगाना में नीडा के तहत वित्तपोषित भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल परियोजनाओं को पुनर्वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा.

सामाजिक बॉण्ड का लिस्टिंग समारोह

ईएसजी = पर्यावरणीय, सामाजिक, अभिशासन; नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता.

10.1 निधियों के स्रोत

10.1.1 पूंजी, प्रारक्षित निधियाँ, और एनआरसी निधियाँ

नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार 13.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 85.7% बढ़कर ₹4.9 लाख करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019) से ₹9.1 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2024) हो गया है. 31 मार्च 2024 को हमारी चुकता पूंजी ₹17,080 करोड़ थी, जबकि प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹30,000 करोड़ थी (चित्र 10.1). वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में, स्वाधिकृत निधियाँ (पूंजी, प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष) ₹72,867 करोड़ थीं. नाबार्ड ने राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि में प्रत्येक में ₹1 करोड़ का योगदान दिया.

नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार 13.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 85.7% बढ़कर ₹4.9 लाख करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019) से ₹9.1 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2024) हो गया है.

10.1.2 जमाराशियाँ

नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण में कमी का लाभ उठाकर समय के साथ विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न निधियों में वृद्धि की. 31 मार्च 2024 को, ऐसी निधियों के तहत कुल बकाया राशि ₹3 लाख करोड़ से अधिक थी, जो कि कुल देनदारियों का 33.2% है, जिनमें अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि, अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमाराशि, दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि और ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) शामिल हैं (चित्र 10.1).

चित्र 10.1: निधियों के स्रोत

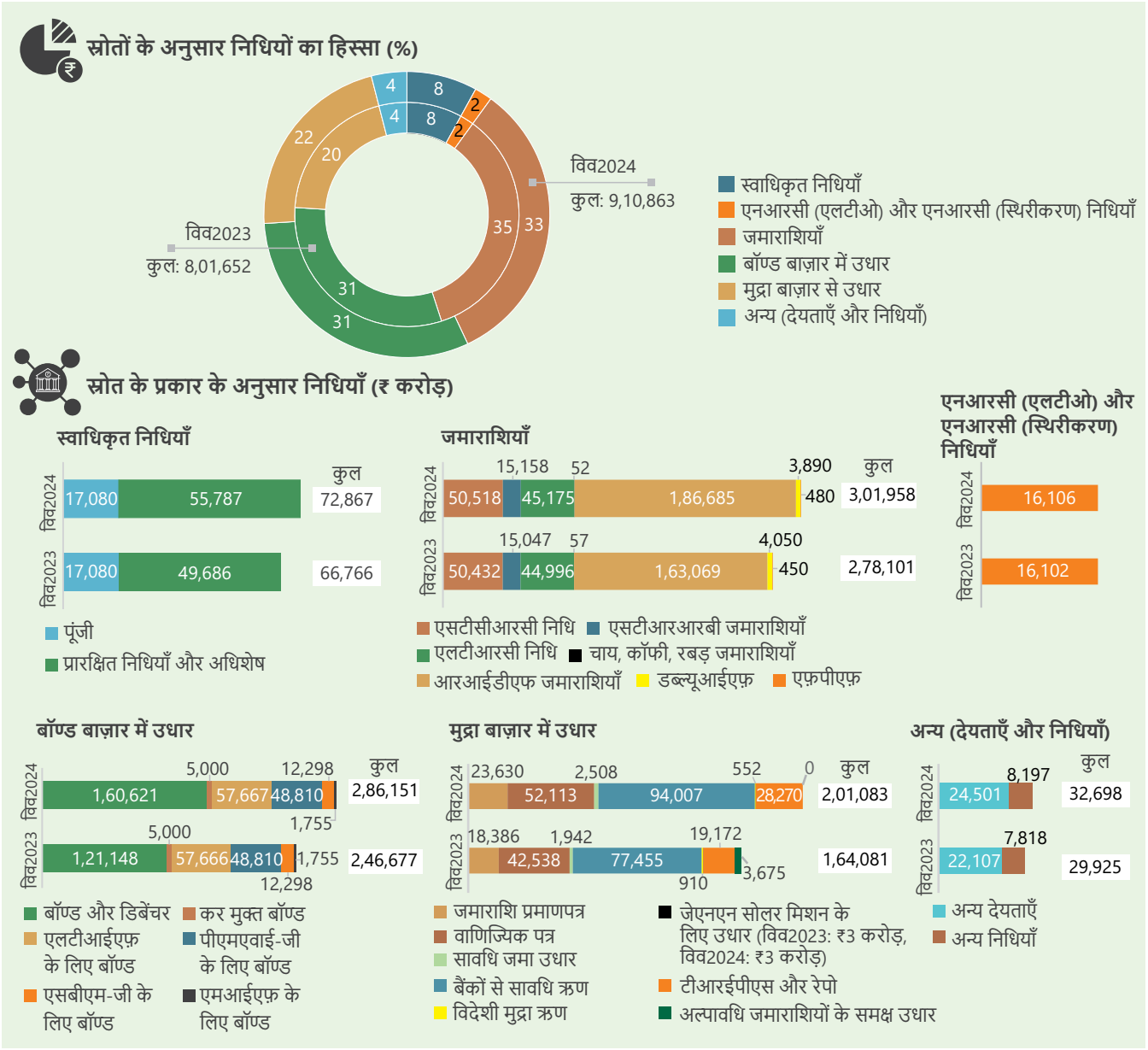

एफ़पीएफ़ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन, एलटीआईएफ़ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एलटीओ = दीर्घावधि परिचालन, एलटीआरसी = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण, एमआईएफ़ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, एनआरसी = राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण, पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आरआईडीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, एसटी = अल्पावधि, एसटीसीआरसी = अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण, एसटीआरआरबी = अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीआरईपीएस = ट्राई-पार्टी रेपो डीलिंग एण्ड सेटलमेंट, डबल्यूआईएफ़ = भंडारागार आधारभूत संरचना निधि.

नाबार्ड ने ग्रामीण उत्पादन और निवेश, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, सामाजिक क्षेत्र विकास, नकदी और निवेश प्रबंधन तथा अचल आस्तियों के सृजन के लिए आधार स्तरीय ऋण बढ़ाने हेतु निधियां जुटाईं.

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में आरआईडीएफ के लिए ₹40,475 करोड़ आबंटित किए. वित्तीय वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने आरआईडीएफ की जमाराशियों के तहत विभिन्न खेपों में ₹49,730 करोड़ जुटाए और ₹25,598 करोड़ चुकाए.

नाबार्ड ने खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) जमाराशियों के तहत भी वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹100 करोड़ जुटाए और ₹70 करोड़ चुकाए. वित्त वर्ष 2024 के अंत में भंडारागार आंधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ) के तहत बकाया जमा राशि ₹3,890 करोड़ और एफपीएफ के तहत ₹480 करोड़ थी.

10.1.3 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार उधार

कुल जुटाई गई राशि ₹3.5 लाख करोड़ थी और नाबार्ड की कुल बकाया उधारी ₹4.9 लाख करोड़ थी. नाबार्ड के कुल उधार पोर्टफोलियो में वाणिज्यिक पत्र, सावधि ऋण और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का हिस्सा 94% था.

बॉण्ड बाज़ार में उधार

- वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹65,393 करोड़ के बॉण्ड जारी किए गए और ₹25,920 करोड़ के बॉण्ड भुनाए गए. बॉण्ड और डिबेंचर के तहत बकाया राशि वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 32.6% बढ़ी.
- वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत सरकार की अतिरिक्त बजटीय संसाधन योजना के तहत कोई भी राशि जुटाई नहीं गई. इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार की योजनाओं के लिए जुटाए गए बॉण्ड के समक्ष बकाया राशि पिछले वर्ष की तरह यथावत् रही.

मुद्रा बाज़ार में उधार

वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने ₹1.3 लाख करोड़ जुटाने के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी किए. वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों से ₹82,450 करोड़ के सावधि ऋण लिए गए.

10.2 निधियों का उपयोग

नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान अपने विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए धन जुटाया, जिनमें ग्रामीण उत्पादन और निवेश, आधारभूत संरचना का निर्माण, सामाजिक क्षेत्र के विकास, नकदी और निवेश प्रबंधन और अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) को बढ़ाना शामिल है (चित्र 10.2).

नाबार्ड किसानों की अल्पकालिक मौसमी कृषि गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) बढ़ाने तथा विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए पूंजी के निर्माण में निवेश करने के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम प्रदान करता है.

बुनकरों और कारीगरों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, विभिन्न ऋण सीमाओं के तहत विपणन सहायता तथा प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अल्पावधि ऋणों को मध्यम अवधि ऋणों में परिवर्तित करने जैसे प्रयोजनों के लिए भी पुनर्वित्त उपलब्ध है.

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों सहित विभिन्न संस्थाओं को आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, सामाजिक क्षेत्र के विकास, भंडारण गतिविधियों, खाद्य प्रसंस्करण आदि हेतु ऋण प्रदान करता है.

नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में योगदान के लिए एनआरसी (एलटीओ) के तहत राज्य सरकारों को सीधे ऋण देता है. इन निधियों का उपयोग नकदी और निवेश प्रबंधन तथा व्यवसाय संचालन के लिए अचल आस्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है.

चित्र 10.2: निधियों का उपयोग

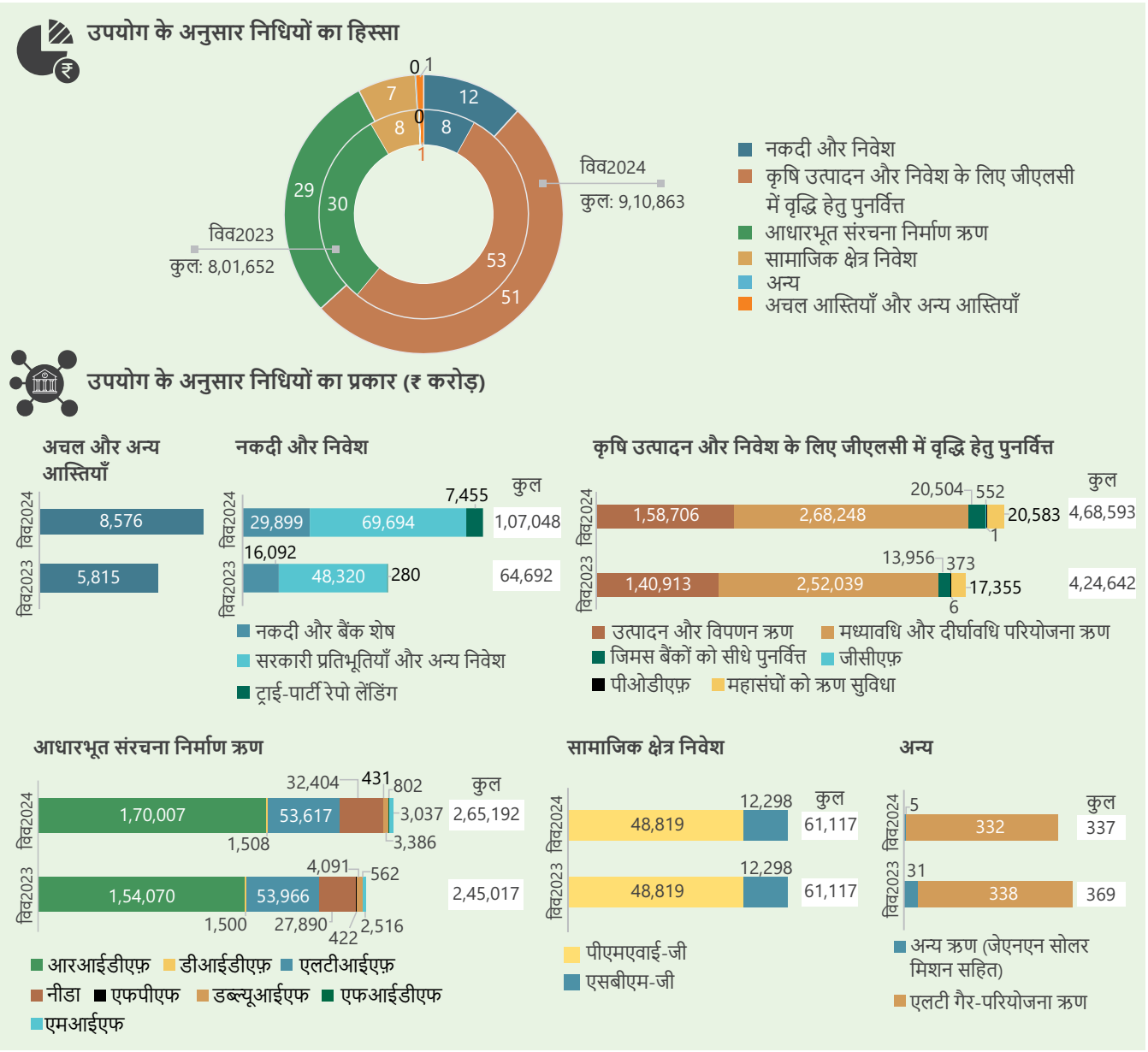

डीसीसीबी = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एफपीएफ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, जीसीएफ = हरित जलवायु निधि, जीएलसी = आधार स्तरीय ऋण, जेएनएन सौर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, एलटी = दीर्घावधि, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, एमटी = मध्यावधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी = प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण, पीओडीएफ = उत्पादक संगठन विकास निधि, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण, डब्ल्यूआईएफ = भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि

नोट: एमटी और एलटी परियोजना ऋणों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के विशेष विकास ऋणपत्रों में अभिदान की गई राशि शामिल है, जो कि अग्रिम के रूप में मानी गई है.

नाबार्ड द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों और अग्रिमों के समक्ष 31 मार्च 2024 तक निधियों के वितरण और वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के मुख्य बिंदु चित्र 10.3 में दिए गए हैं.

चित्र 10.3: पुनर्वित्त के माध्यम से आधार स्तरीय ऋण में वृद्धि: 31 मार्च 2024 की स्थिति

- **जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा के तहत ऋण** वित्तीय वर्ष 2024 में 46.9% बढ़कर ₹20,504 करोड़ हो गया.
- कुल ऋण और अग्रिमों में **मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋणों** की हिस्सेदारी सर्वाधिक 33.7% थी. **उत्पादन और विपणन ऋण** की हिस्सेदारी लगभग 20% थी. इन दो मदों में उच्च वृद्धि और आस्तियों में उच्च हिस्सेदारी दर्ज की गई.
- 31 मार्च 2024 को **सीएफएफ** ₹20,583 करोड़ पर पहुंच गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 18.6% की वृद्धि दर्ज की गई.
- बैंकों द्वारा प्रदान किए गए **मध्यावधि और दीर्घावधि निवेश ऋण** ₹2.7 लाख करोड़ तक पहुंच गए, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 6.4% अधिक हैं.

- वित्तीय वर्ष 2024 में **कुल ऋण और अग्रिम** ₹8 लाख करोड़ थे, जो वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 8.8% अधिक रहे.
- **आधार स्तर पर ऋण देने के लिए उपलब्ध संसाधनों** में 12.6% की वृद्धि हुई क्योंकि अल्पावधि (मौकृप) और अल्पावधि (मौकृप से इतर) (उत्पादन और विपणन ऋण) बकाया वित्तीय वर्ष 2024 में ₹1.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया.
- **राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि (मौकृप)** ₹89,765 करोड़ (72.8%), **क्षेत्रा बैंकों को** ₹33,367 करोड़ (27.1%), **तथा रासकृग्रावि बैंकों को** ₹100 करोड़ (0.1%) रहा.
- ₹35,474 करोड़ का **अल्पावधि (मौकृप से इतर)** रास बैंकों (71.8%), क्षेग्रा बैंकों (28%), और लघु वित्त बैंकों (0.22%) द्वारा प्राप्त किया गया.

सीएफएफ = महासंघों को ऋण सुविधा, डीसीसीबी = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जीएलसी = आधार स्तरीय ऋण, एलटी = दीर्घावधि, एमटी = मध्यावधि, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, एसएफबी = लघु वित्त बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, एसटी (ओएसएओ) = अल्पावधि (मौकृप से इतर), अल्पावधि (मौकृप) = अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन
नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आंकड़े हैं

चित्र 10.4: 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सामाजिक क्षेत्र निवेश

एसबीएम – जी के अंतर्गत **₹12,298 करोड़ का एक्सपोज़र**

पीएमएवाई – जी के अंतर्गत **₹48,819 करोड़ के बकाया ऋण** एनआरआईडीए को दिए गए (आस्तियों के 5.4%)

एनआरआईडीए = राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, एसबीएम-जी=स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण.
नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आंकड़े हैं.

चित्र 10.5: 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आधारभूत संरचना वित्त

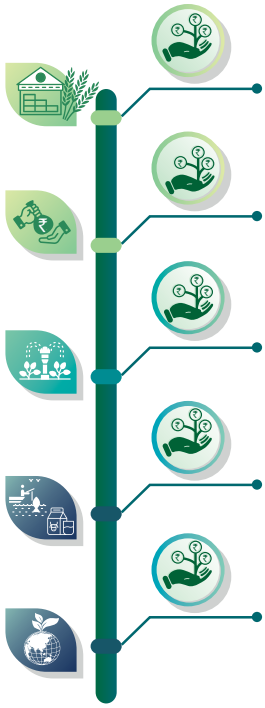

आरआईडीएफ परियोजनाओं के लिए ऋण (आस्तियों का 20%): 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ₹1.7 लाख करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 10.3% की वृद्धि.

वित्तीय वर्ष 2024 में ₹32,404 करोड़ के **नीडा ऋण,** जो गत वर्ष की तुलना में 16.2% अधिक हैं.

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार **एलटीआईएफ़ ऋण** ₹53,617 करोड़ हो गए.

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार **अन्य आधारभूत संरचना ऋण** ₹8,732.5 करोड़ (अर्थात् डबल्यूआईएफ़ ₹3,385.9 करोड़, डीआईडीएफ़ ₹1,508.2 करोड़, एमआईएफ़ ₹3,036.9 करोड़ और एफ़आईडीएफ़ ₹801.5 करोड़) हो गए, जिनमें 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई.

वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 48% की वृद्धि दर्ज करते हुए **जीसीएफ़ ऋण** ₹552 करोड़ हो गए, जिससे हरित विकास का बीजारोपण हुआ.

डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, जीसीएफ = ग्रीन क्लाइमेट फंड, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, डब्ल्यूआईएफ = भंडारागार आधारभूत संरचना निधि.
नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आंकड़े हैं.

चित्र 10.6: 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अधिशेष निधियों का निवेश

बैंकों में जमाराशि सहित विभिन्न वित्तीय लिखतों में निवेशित अल्पावधि अधिशेष राशि ₹92,284 करोड़ थी.

75.5% सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय साधनों में लगाया गया .

चलनिधि और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **₹22,590 करोड़** अल्पावधि बैंक जमा के रूप में रखे गए.

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आंकड़े हैं.

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 24% वृद्धि के साथ ₹48,847 करोड़ की आय अर्जित की.

10.3 आय और व्यय

नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹48,847 करोड़ की आय अर्जित की, जो वित्तीय वर्ष 2023 की आय से 24% अधिक है (चित्र 10.7). वित्तीय वर्ष 2024 में नाबार्ड का कर-पूर्व लाभ ₹8,068 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023 के ₹6,555 करोड़ की तुलना में) और कर-पश्चात् लाभ ₹6,103 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023 में ₹5,360 करोड़ की तुलना में) था. निवल अधिशेष को नाबार्ड ने अपनी विभिन्न निधियों, यथा-अनुसंधान एवं विकास निधि, प्रारक्षित निधि, एनआरसी (एलटीओ) निधि, और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि आदि में स्थानांतरित करके विनियोजित किया है.

चित्र 10.7: आय विश्लेषण

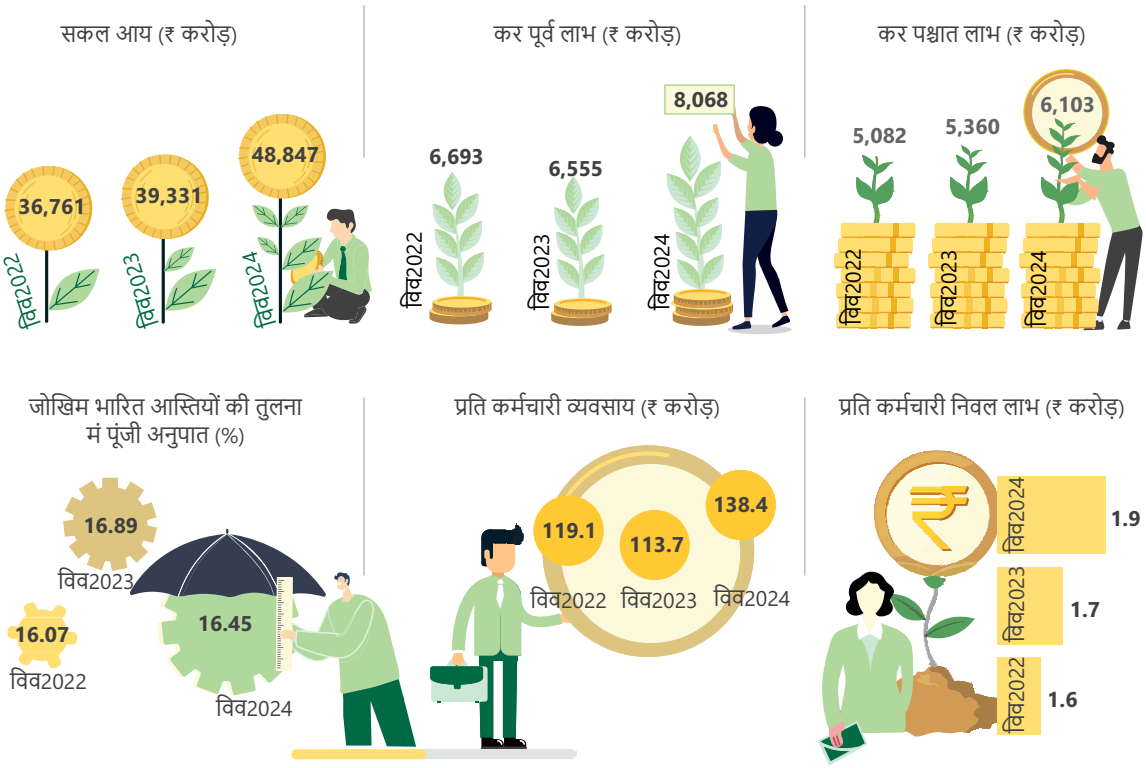

10.4 कृषि और ग्रामीण व्यवस्था में नाबार्ड के निवेश

नाबार्ड इक्विटी निवेश के माध्यम से रणनीतिक भागीदारों के साथ सहयोग करता है ताकि ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के साथ-साथ कृषि और ग्रामीण पारितंत्र के विकास हेतु सहयोग प्रदान किया जा सके.

10.4.1 नाबार्ड की सहायक संस्थाओं में निवेश

नाबार्ड ने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सात सहायक कंपनियों की स्थापना की है. ये सहायक कंपनियाँ नाबार्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों के वित्तपोषण के माध्यम से, ग्रामीण और कृषि विकास में नाबार्ड की भूमिका का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. ये सूक्ष्म ऋण सुविधाएँ, ऋण गारंटी प्रदान करती हैं, ग्रामीण स्टार्ट-अप में निवेश करती हैं, परामर्श प्रदान करती है, और ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्रों में नवोन्मेष करती हैं.

31 मार्च 2024 तक सात सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी में कुल निवेश ₹604.7 करोड़ था (चित्र 10.8). वित्त वर्ष 2024 में नाबार्ड को नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड से ₹7.5 करोड़, नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड से ₹2.3 करोड़, नैबफिन्स लिमिटेड से ₹10.2 करोड़ और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ₹0.1 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ.

चित्र 10.8: नाबार्ड की सहायक कंपनियों में शेयरधारिता (₹ करोड़)

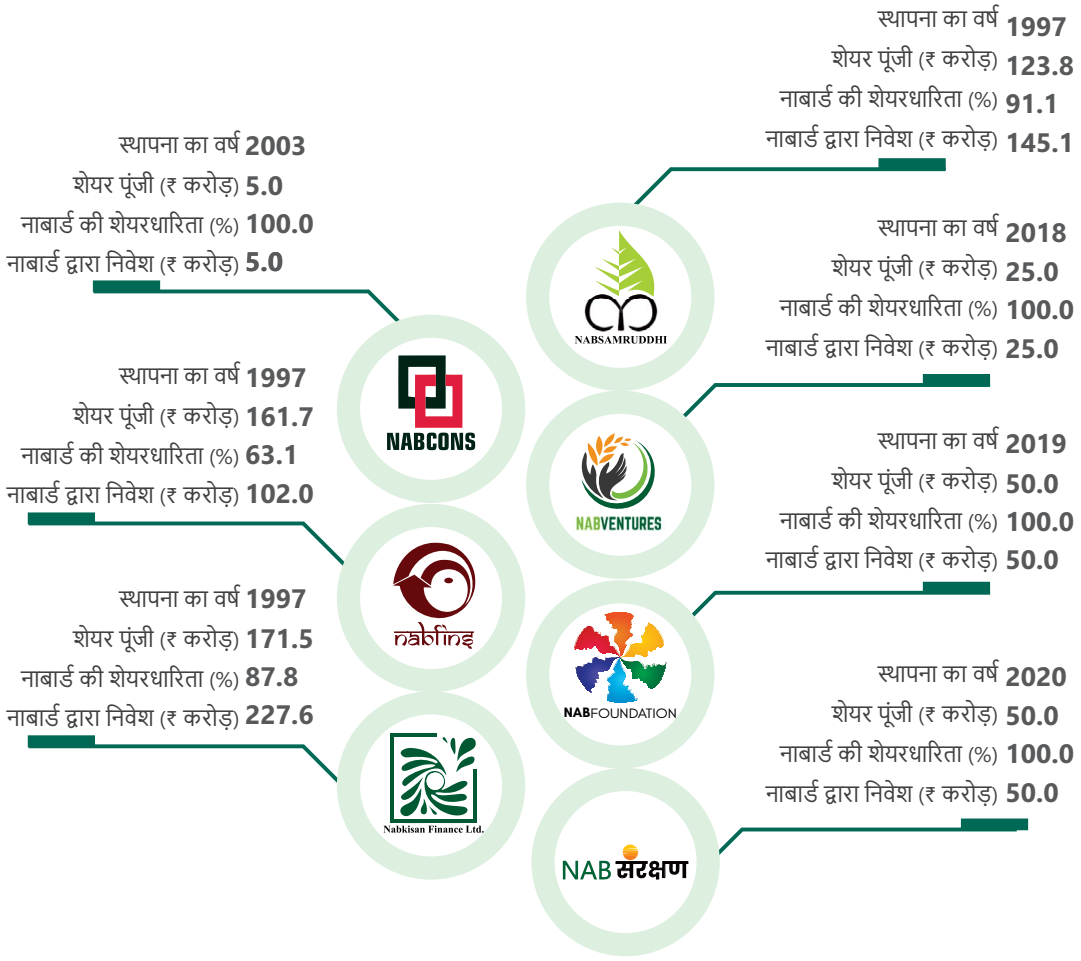

नोट: नैबकिसान और नैबसमृद्धि के आंकडों में प्रीमियम शामिल है.

10.4.2 रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ

नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शामिल कंपनियों की इक्विटी में रणनीतिक रूप से निवेश किया है. इन निवेशों का उद्देश्य उन संस्थाओं को सहायता प्रदान करना है जो कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान देती हैं, चाहे प्रत्यक्ष सहयोग के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से—कृषि जोखिमों को कम कर, बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर, आवश्यक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर, कौशल उन्नयन कर और विशेष संस्थागत तंत्रों के माध्यम से ऋण की पहुंच में सुधार कर.

31 मार्च 2024 तक, नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली दस कंपनियों में ₹1,106.2 करोड़ का निवेश किया था. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, नाबार्ड को चार कंपनियों से ₹23.7 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ, जिनमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (20%, ₹10.6 करोड़), भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (20%, ₹12 करोड़), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (191%, ₹0.7 करोड़) और कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (6%, ₹0.3 करोड़) शामिल हैं.

तालिका 10.1: रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ

क्रम सं	*कंपनी*	*निवेश का वर्ष*	*नाबार्ड का निवेश (₹ करोड़)*	*हिस्सा (%)*
1	एएफ़सी इंडिया लिमिटेड.	वित्त2000	1.0	6.7
2	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमि.	वित्त2004	60.0	30.0
3	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक.*	वित्त 2003 और वित्त 2018	966.3	9.4
4	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्श्चेज लिमि.*	वित्त 2004	16.9	11.1
5	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड.	वित्त 2006	0.3	0.7
6	सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमि.*	वित्त 2016	9.8	9.4
7	नेशनल ई- गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमि.	वित्त 2017	1.5	2.0
8	एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया	वित्त 2017	0.0	4.0
9	नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमि.	वित्त 2018	10.5	13.0
10	ओपेन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स	वित्त 2022 और 2024	40.0	5.3
कुल			**1,106.2**	

* आकड़ों में प्रीमियम शामिल है.
नोट: संभव है पूर्णांकन के कारण घटकों का योग, कुल के बराबर न हो.

10.4.3 वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश

नाबार्ड वैकल्पिक निवेश निधि (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत) में योगदान दे रहा है, ताकि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान अथवा नई गतिविधियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जा सके, ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अनुकरण के लिए आय-उत्पादक टिकाऊ इकाइयों के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके तथा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों और प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके.

31 मार्च 2024 तक, 31 निधियों में नाबार्ड की कुल प्रतिबद्धता ₹729 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 25 निधियों में यह प्रतिबद्धता ₹634 करोड़ की थी. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, नाबार्ड ने 6 निधियों को ₹95 करोड़ देने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है. ₹503.3 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है. इन निधियों ने कुल ₹103.2 करोड़ की राशि आहरित की और वर्ष के दौरान ₹15.1 करोड़ की पूंजी वापस की, जिसमें ₹7.1 करोड़ का पूंजीगत लाभ और ₹5.7 करोड़ के लाभांश सहित अन्य आय शामिल है.

10.4.4 अन्य पहलें

- 6 मार्च 2024 को मुंबई में 'हार्नेसिंग ऑपर्च्यूनिटीज़: नाबार्ड ट्रान्स्फ़ोर्मिंग एग्री-लैंडस्केप' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्यम पूंजीपतियों, उद्योग विशेषज्ञों, इनक्यूबेशन केंद्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ), कृषि-स्टार्ट-अप संस्थापकों और इनक्यूबेटीज़ को कृषि-स्टार्ट-अप के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना था.

- नाबार्ड के परिचालन और पोर्टफोलियो कंपनियों की कार्यप्रणाली के बीच तालमेल विकसित करने के लिए, नाबार्ड ने नैबवेंचर्स के साथ मिलकर इन कंपनियों की एक बैठक आयोजित की.
- सहायक कंपनियों में प्रभावी कॉर्पोरेट अभिशासन की दृष्टि से, नाबार्ड ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ में अपनी सहायक कंपनियों के नामिती निदेशकों/ प्रबंध निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया.

नाबार्ड को उम्मीद है कि कृषि-निर्यात मूल्य शृंखला वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में प्रगतिशील निवेश के अवसरों का लाभ उठाएगा.

10.5 प्रभाव और प्रगति के लिए रणनीतिक निवेश और संग्रहण

नाबार्ड, विकास की गतिविधियों के वित्तपोषण और एक सुव्यवस्थित रूप से विविधीकृत, विस्तारित और बेहतर प्रदर्शन करने वाली आस्तियों को आधार बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् विकास की दिशा में, नाबार्ड ने पेयजल परियोजना के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु उपयोग किए जाने वाले सामाजिक बॉण्ड जारी किए हैं. यह विविधीकरण 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने के उद्देश्य से सामाजिक और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए नाबार्ड की गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है. आने वाले वर्षों में, नाबार्ड को उम्मीद है कि कृषि-निर्यात, मूल्य शृंखला वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन आदि में निवेश के अवसरों का और लाभ उठाएगा.

अध्याय 10 के अनुबंध: वित्तीय वर्ष 2024 में नाबार्ड की सहायक कंपनियों का कार्यनिष्पादन

नैबफ़िन्स

नैबफ़िन्स लिमिटेड (नैबफ़िन्स) ने वित्त वर्ष 2024 में ₹2,723 करोड़ का संवितरण करते हुए उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 48% की मजबूत वृद्धि दर को दर्शाता है. 31 मार्च 2024 तक, तुलन-पत्र का आकार ₹3,112.4 करोड़ और बकाया ऋण ₹3,050 करोड़ था. वित्त वर्ष 2024 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹191.6 करोड़ है. कंपनी के पास 11 लाख से अधिक सक्रिय उधारकर्ता हैं. 31 मार्च 2024 के अंत में नैबफ़िन्स की सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 2.1% थीं.

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 75 नई प्रत्यक्ष ऋण शाखाएँ खोलकर अपनी पहुँच का विस्तार किया, जिससे शाखाओं की कुल संख्या 402 हो गई. उत्तर प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में परिचालन शुरू होने के साथ ही नैबफ़िन्स का भौगोलिक क्षेत्र काफी विस्तारित हो गया, जिससे इसकी उपस्थिति 19 राज्यों तक बढ़ गई.

अपनी स्थापना के बाद से, नैबफ़िन्स ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बीच सबसे कम ब्याज दर पर ₹13,966 करोड़ से अधिक के सूक्ष्म-ऋण प्रवाह के साथ 28 लाख से अधिक परिवारों को अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं. कंपनी दो अलग-अलग व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से काम करती है, अर्थात्-व्यवसाय और विकास करेस्पॉन्डेंट मॉडल और प्रत्यक्ष ऋण मॉडल. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं तक पहुँचने के लिए अन्य संस्थाओं के प्रयासों में सहायता हेतु, कंपनी संस्थागत ऋण मॉडल के तहत थोक ऋण भी प्रदान करती है. वर्तमान में, कंपनी की 401 शाखाएँ और 109 सक्रिय बिज़नेस करेस्पॉण्डेंट साझेदार हैं.

वित्तीय वर्ष 2024 में प्रमुख पहलें

वित्तीय वर्ष 2024 की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं

- केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में तीन पूर्णतः महिला शाखाएँ खोलना;
- उधारकर्ताओं को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना; और
- नाबार्ड के सहयोग से महिला उधारकर्ताओं के कौशल विकास के लिए पांच परियोजनाएं.

उत्तर प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में परिचालन शुरू होने के साथ ही नैबफ़िन्स का भौगोलिक क्षेत्र काफी विस्तारित हो गया, जिससे इसकी उपस्थिति 19 राज्यों तक बढ़ गई.

पुरस्कार

- नैबफ़िन्स को अपनी अभूतपूर्व डेटा प्रभावोत्पादकता के लिए अग्रणी क्रेडिट सूचना कंपनी सीआरआईएफ हाई मार्क से डेटा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है,
- तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के नामक्कल जिले में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) से संबंधित पहलों के लिए नैबफ़िन्स की सराहना की. सीएसआर प्रतिबद्धताओं के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने देश भर के आठ राज्यों में ₹1.2 करोड़ की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

शोकेस अ10.1: विजन से उद्यम तक: नैबफ़िन्स से सहायता प्राप्त उद्यमी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं

छत्तीसगढ़ की सुलोचना साव ने स्नैक बनाने के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उद्यमशीलता यात्रा शुरू की है. संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), जिसकी वह सदस्य थी, के माध्यम से नैबफिन्स के सहयोग से सुलोचना ने अपने उद्यम को उल्लेखनीय सफलता की ओर अग्रसर किया. अपनी अटूट प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से, उन्होंने न केवल अपने उद्यम का विस्तार किया है, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया है और आर्थिक विकास को गति दी है.

सुलोचना साव, राजगढ़, छत्तीसगढ़ के संयुक्त देयता समूह की सदस्य

नैबकिसान

नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड (नैबकिसान) के तुलन-पत्र का आकार ₹2,804.5 करोड़ (आईजीएएपी के तहत) हो गया.[1] जो साल-दर-साल 30% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है. ₹2,585.7 करोड़ के सकल ऋण बही बकाया ने साल-दर-साल लगभग 35% की वृद्धि दर्शाई, जबकि कुल मंजूरियाँ और संवितरण निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक थे, जो क्रमशः ₹1,779 करोड़ और ₹1,732 करोड़ तक पहुंच गए. 31 मार्च 2024 तक, नैबकिसान ने कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ₹779.9 करोड़ के 3,004 ऋण मंजूर किए हैं. कुल मिलाकर, 20 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 1.5 मिलियन किसान, नैबकिसान के माध्यम से प्रभावित हुए हैं.

नैबकिसान, भारत सरकार की कृषि आधारभूत संरचना वित्तपोषण (एआईएफ) योजना के तहत एफपीओ को ऋण देने वाली अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) बनी हुई है. वर्ष के दौरान, नैबकिसान ने एआईएफ के तहत ₹4.9 करोड़ मूल्य के 24 ऋण मंजूर किए, जिसमें एक कृषक उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मंजूर करना भी शामिल है. इसके साथ ही, नैबकिसान ने एआईएफ के तहत संचयी रूप से ₹15.2 करोड़ की राशि के 102 एफपीसी ऋण मंजूर किए हैं. वर्ष के दौरान, नैबकिसान ने ₹93 लाख मूल्य की तीन सामाजिक रूप से प्रासंगिक सीएसआर परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया.

तमिलनाडु सरकार की तीन एफपीसी वित्तपोषण योजनाओं के कार्यान्वयन में साझेदार के रूप में, नैबकिसान ने वर्ष के दौरान 143 एफपीसी को ₹15.5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की. नैबकिसान ने परियोजना के तहत प्रवर्तित और सहायता प्राप्त एफपीओ को ऋण लिंकेज में सक्षम करने के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 'तमिलनाडु ग्रामीण परिवर्तन परियोजना', तमिलनाडु सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं. इसके अलावा, एफपीओ के लिए ओडिशा क्रेडिट गारंटी योजना के कार्यान्वयन में साझेदार के रूप में, नैबकिसान ने 114 एफपीओ को ₹9.2 करोड़ की राशि की ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया है.

तमिलनाडु सरकार की तीन एफपीसी वित्तपोषण योजनाओं के कार्यान्वयन में साझेदार के रूप में, नैबकिसान ने वर्ष के दौरान 143 एफपीसी को ₹15.5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की.

कृषि क्षेत्र के प्रौद्योगिकी अभिमुखीकरण में सुधार लाने के लिए, नैबकिसान ने विल्ग्रो इनोवेशन फाउंडेशन के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विल्ग्रो द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट-अप को वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विल्ग्रो ऋण मूल्य के 15% से 25% तक की जोखिम-मुक्त पूंजी प्रदान करेगा. इस संदर्भ में, नैबकिसान ने कृषि स्टार्ट-अप को ₹2 करोड़ के दो ऋण मंजूर किए हैं.

नैबकिसान एफपीओ वित्तपोषण के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के तहत एक ऋण देने वाली पात्र संस्था (ईएलआई) है, जिसका प्रबंधन नैबसंरक्षण द्वारा किया जाता है. इस योजना के तहत, वर्ष के दौरान 619 एफपीसी को ₹123.4 करोड़ की ऋण गारंटी दी गई.

नैबसमृद्धि

नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (एनएसएफ़एल) का वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान रिकॉर्ड-तोड़ वित्तीय प्रदर्शन रहा, जिसमें तुलन-पत्र में साल-दर-साल 60% की वृद्धि हुई और तुलन-पत्र ₹1,855 करोड़ का हो गया, और प्रबंधन के तहत आस्तियाँ ₹1,804 करोड़ हो गईं. और करों के बाद लाभ में 39% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह ₹49 करोड़ हो गई, जो लक्ष्य से 18% अधिक है. कंपनी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, तथा ऋण बही में संग्रह और विस्तार के माध्यम से बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 0.5% (31 मार्च 2023 तक) से घटकर 0.14% (31 मार्च 2024 तक) हो गया. कंपनी लगातार दूसरे वर्ष भी देनदारी को 'शून्य' रखने में सफल रही. वर्ष के दौरान ऐसे घटक जिन पर बल दिया जा रहा है उनके लिए कुल संवितरण में से लगभग 35% संवितरण किया गया. कुल मिलाकर, 32 साझेदारों के माध्यम से लगभग ₹350 करोड़ के जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (वॉश) ऋण वितरित किए गए. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान स्वीकृत राशि ₹191 करोड़ थी, जो कि वर्ष दर वर्ष 100% की वृद्धि दर्शाती है. नैबसमृद्धि एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य संस्थागत ग्राहकों के माध्यम से कुल मिलाकर 25 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने में सक्षम रही है.

वित्तीय वर्ष 2024 की प्रमुख पहलें

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान एनएसएफ़एल की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- एनएसएफएल ने सितंबर 2023 में Water.org के साथ संयुक्त रूप से एक वॉश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, ताकि वॉश और वित्तीय क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर क्लाइमेट-रेडी वॉश ऋण के दिशानिर्देशों, अवसरों और चुनौतियों के साथ-साथ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहलुओं पर चर्चा की जा सके.
- इसके अलावा, एनएसएफएल ने 8 और 9 नवंबर 2023 को आयोजित समावेशी विकास पर सा-धन राष्ट्रीय सम्मेलन को सह-प्रायोजित किया और इस वार्षिक कार्यक्रम में पहला वॉश (डब्ल्यूएएसएच) वित्त पैनल सत्र शुरू किया. कार्यक्रम के दौरान, एनएसएफएल के अग्रणी क्लाइमेट-रेडी वॉश फंडिंग कार्यक्रम को नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी के.वी. ने लॉन्च किया. इस प्रायोगिक कार्यक्रम को नाबार्ड से विशेष रियायती पुनर्वित्त और सा-धन, Water.org और फिनिश मोंडियल जैसे ज्ञान साझेदारों से तकनीकी सहायता प्राप्त है.
- एनएसएफएल ने जलवायु-अनुकूल वॉश ऋण को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट ऑफ पीपल के माध्यम से फिनिश मोंडियल के साथ सहयोग करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
- नाबार्ड की अनुदान सहायता के साथ, एनएसएफएल ने ट्रस्ट ऑफ पीपल के सहयोग से, 22 मार्च 2024 से 7 राज्यों में जलवायु संवेदनशील जिलों में एमएफआई के ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए अपने प्रयोगिक कार्यक्रम के तहत एक क्लाइमेट-रेडी वॉश जागरूकता अभियान शुरू किया है.
- इसके अलावा, जलवायु वित्तपोषण को आगे बढ़ाने के लिए विश्व जल दिवस पर क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के साथ एक सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए.
- वर्ष के दौरान, एनएसएफएल ने वॉश घटक तथा शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए ₹69.02 लाख की राशि की तीन सीएसआर परियोजनाओं को सहायता प्रदान की.

नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (एनएसएफ़एल) का वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान रिकॉर्ड-तोड़ वित्तीय प्रदर्शन रहा, जिसमें तुलन-पत्र में साल-दर-साल 60% की वृद्धि हुई और तुलन-पत्र ₹1,855 करोड़ का हो गया. प्रबंधन के तहत आस्तियाँ ₹1,804 करोड़ हो गईं. और करों के बाद लाभ में 39% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह ₹49 करोड़ हो गई, जो लक्ष्य से 18% अधिक है.

पुरस्कार

एनएसएफ़एल, वॉश निधीयन में एक पारिस्थितिकीय तंत्र निर्माता के रूप में उभरा है-

- घरेलू रूप से विकसित एनबीएफसी के बीच सतत विकास लक्ष्य 6 के लिए सबसे बड़े थोक ऋण प्रदाता के रूप में,
- अंतिम छोर की वॉश परियोजनाओं के लिए सबसे बड़े थोक ऋण वित्तपोषक के रूप में,
- क्लाइमेट-रेडी वॉश फंडिंग में अग्रणी संस्था के रूप में, और

- सभी क्षेत्रों (सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम [एमएसएमई], और किफायती/ ग्रामीण आवास) और वॉश के अंतर्गत संपूर्ण जोखिम रेटिंग स्पेक्ट्रा (बिना रेटिंग वाली एनबीएफसी, गैर-लाभकारी और ट्रस्ट सहित) को कवर करने वाले एकमात्र घरेलू थोक ऋण प्रदाता के रूप में.

सम्मान स्वरूप, एनएसएफएल को पूंजी प्रदाता श्रेणी के अंतर्गत, लगातार दूसरी बार, सा-धन Water.org 'जल एवं स्वच्छता वित्तपोषण पुरस्कार, 2023' से सम्मानित किया गया.

शोकेस अ10.2: सूक्ष्म ऋण, व्यापक परिवर्तन

अपने समुदाय के कई अन्य लोगों की तरह, कर्मिना बीबी की भी पहले उचित जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (वॉश) सुविधाओं तक पहुँच नहीं थी, जिससे उन्हें बीमारियों का खतरा रहता था और असुविधा होती थी. जब नैबसमृद्धि ने अपने वॉश पोर्टफोलियो में पहली अनरेटेड इकाई, ग्रामीण शक्ति माइक्रोफाइनेंस को रियायती ऋण दिया, तो ग्रामीण शक्ति माइक्रोफाइनेंस ने कर्मिना को एक नया शौचालय बनाने के लिए ऋण दिया. शौचालय ने न केवल उसके परिवार की स्वच्छता की आदतों में सुधार किया, बल्कि उनकी सुख-सुविधा और सम्मान को भी बढ़ाया.

कर्मिना बीबी, अपने नवनिर्मित शौचालय के पास

नैबकॉन्स

वित्त वर्ष 2024 में, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में 63% की वृद्धि देखी, जो ₹231.8 करोड़ तक पहुंच गया.

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के लिए पसंदीदा परामर्शदाता के रूप में, नैबकॉन्स जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान देता है.

वित्त वर्ष 2024 में, नैबकॉन्स ने इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण डोमेन के तहत अपनी सेवाएँ प्रदान करके अपने उत्पादों का विस्तार किया. नैबकॉन्स को सहकारी क्षेत्र में भारत सरकार की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत कई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में गोदामों/ साइलो/ प्रसंस्करण केंद्रों/ सामान्य हायरिंग केंद्रों के निर्माण की परियोजना सौंपी गई थी. नैबकॉन्स ने भारत सरकार के 'सहकार से समृद्धि' (बॉक्स अ10.1) के दृष्टिकोण के तहत 11 राज्यों में 11 गोदामों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया.

भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन 2021-25 के तहत केरल सरकार के लक्ष्यों में योगदान प्रदान करने हेतु नैबकॉन्स ने केरल राज्य की कृषि के लिए एकीकृत कृषि डेटा हब और डिजिटल किसान सेवाएँ प्लैटफॉर्म स्थापित किया है.

वित्त वर्ष 2024 में, नैबकॉन्स ने इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण डोमेन के तहत अपनी सेवाएँ प्रदान करके अपने उत्पादों का विस्तार किया.

वित्त वर्ष 2024 में अन्य प्रमुख कार्य

- गोवा और कर्नाटक में छोटे किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क
- महाराष्ट्र और कर्नाटक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता
- महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी

बॉक्स अ10.1: नैबकॉन्स ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत गोदामों के निर्माण की प्रयोगिक परियोजना शुरू की

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना मई 2023 में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है. इस योजना का लक्ष्य देश में अनाज भंडारण सुविधाओं की कमी को दूर करना और भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है. इस योजना के अंतर्गत, अगले 5 वर्षों में ₹1.25 लाख करोड़ की अनुमानित लागत से 700 लाख मीट्रिक टन की विशाल भंडारण क्षमता बनाई जाएगी. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर भंडारण सुविधाएँ स्थापित करके, सरकार का लक्ष्य एक विकेंद्रीकृत भंडारण नेटवर्क तैयार करना है.

योजना का व्यावसायिक रूप से समयबद्ध और एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 11 गोदामों/ प्रसंस्करण केंद्रों/ कस्टम हायरिंग केंद्रों के निर्माण का कार्य नैबकॉन्स को सौंपा, साथ ही साइट पर व्यवहार्यता अध्ययन करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने का भी कार्य सौंपा. प्रयोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, नैबकॉन्स ने नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ सहयोग किया.

आंतरिक परामर्शदाताओं और विशेष साझेदार एजेंसियों की एक विशेषज्ञ टीम के साथ, नैबकॉन्स ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 11 गोदामों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया और इस अग्रणी कदम के साथ इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश किया. 24 फरवरी 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इन गोदामों का उद्घाटन किया और इन गोदामों को देश के किसानों को समर्पित किया.

चित्र बीए10.1: डब्ल्यूएलजीएसपी के अंतर्गत राज्य-वार पैक्स भंडारागार (क्षमता मीट्रिक टन में)

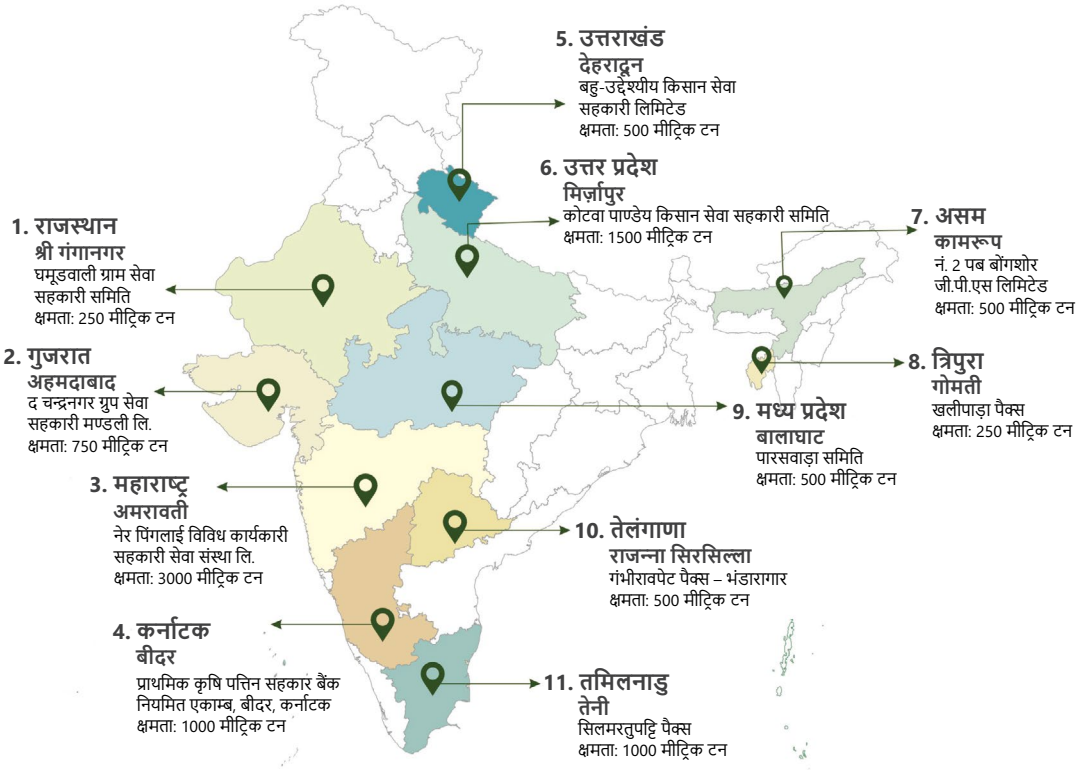

- 5 राज्यों अर्थात् राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम और ओडिशा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना
- पश्चिम बंगाल में पुनरुज्जीवन और शहरी परिवर्तन 2.0 के लिए अटल मिशन के तहत डीपीआर की तैयारी
- स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य (एसडबल्यूएसीएच) परियोजना, राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना डिजाइन एवं प्रबंधन सलाहकार
- उत्तर प्रदेश में एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाने और तेज करने की योजना के तहत रणनीतिक निवेश योजना तैयार करना
- उत्तर प्रदेश में कृषि-ग्रामीण और गंगे ग्राम ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निगरानी, समन्वय और सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना
- ईएनडब्ल्यूआर-आधारित बंधक वित्तपोषण[2] के विकास में आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा के लिए भारतीय भंडारण प्राधिकरण के परिचालन का संपूर्ण अध्ययन
- मृदा जैव प्रौद्योगिकी और प्रकृति-आधारित उपचार का उपयोग करके नमामि गंगे मिशन के तहत पुनरुज्जीवन और संरक्षण के लिए शाहदरा नाले का सर्वेक्षण और जांच
- हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत वित्तीय वर्ष 2017- वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान किए गए कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन
- सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में पूर्ण किए गए सीएसआर कार्यक्रमों/ गतिविधियों का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया

नैबवेंचर्स

नैबवेंचर्स निधि-I ("निधि") नैबवेंचर्स लिमिटेड की पहली फ्लैगशिप निधि है, जिसमें ₹598 करोड़ का पूल्ड कॉर्पस है. एंकर निवेशक के रूप में नाबार्ड ने निधि में ₹228 करोड़ का निवेश किया है, जबकि प्रायोजक के रूप में नैबवेंचर्स ने ₹25 करोड़ का निवेश किया है. यह एक सेक्टर-केंद्रित निधि है जो शुरुआत से लेकर मध्य-चरण में एग्री-टेक, फूड-टेक, एग्री/ रूरल फिनटेक और रूरल टेक व्यवसायों में निवेश करती है. यह रणनीतिक और परिचालन अंतर्दृष्टि, पेशंट कैपिटल और नाबार्ड के व्यापक नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करके इन उद्योगों में परिवर्तन लाती है. वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, निधि ने ₹62 करोड़ की नई निवेश प्रतिबद्धताएँ की हैं. निधि ने अनुवर्ती निवेशों के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो स्टार्ट-अपों को सहयोग प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

स्थापना के बाद से 31 मार्च 2024 तक कुल आहरित निकासी प्रतिबद्धताएं ₹365.7 करोड़ हैं, जो ₹598 करोड़ की कुल राशि का 61% है. स्थापना के बाद से 31 मार्च 2024 तक मंजूर संचयी निवेश ₹320 करोड़ है, जो परिनियोजन योग्य राशि का 60% है.

निवेश-प्राप्त कम्पनियों ने कृषि और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नानुसार प्रभावित किया है:

- जय किसान ने 11 राज्यों में खाद्य और कृषि-व्यवसाय मूल्य शृंखला में ₹3,000 करोड़ के ऋण की सुविधा प्रदान की है.
- कृषितंत्र ने 1 लाख से अधिक किसानों के लिए त्वरित मृदा परीक्षण को सक्षम बनाया है, और कंपनी भारत सरकार की डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए एक अनुमोदित साझेदार है.
- विलकार्ट ने चार राज्यों के 67 जिलों के 23,000 गांवों में 90,000 से अधिक ग्रामीण किराना दुकानों को एक प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से जोड़ा है.
- उन्नति ने कृषि इनपुट और आउटपुट एकत्रीकरण के लिए 181 जिलों में 83,569 दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से 17.2 लाख किसानों को जोड़ा है.
- सत्युक्त द्वारा विकसित एक ऐप वास्तविक समय पर उपग्रह और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर 200 साझेदारों के माध्यम से 4 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए 80 से अधिक फसलों के लिए अनुकूलित फसल सलाह प्रदान करता है; इस तकनीक का उपयोग भारत सहित 19 देशों में किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, नैबवेंचर्स ने ₹62 करोड़ की नई निवेश प्रतिबद्धताएँ की हैं

नैबसंरक्षण

नाबार्ड की सबसे नई सहायक कंपनी नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण) को नवंबर 2020 में एक ट्रस्टी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, ताकि वांछित क्षेत्रों में वित्त के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी निधि का प्रबंधन किया जा सके, जिससे संधारणीय और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान दिया जा सके. वर्तमान में, नैबसंरक्षण दो ऋण गारंटी निधि न्यासों का प्रबंधन कर रहा है: कृषक उत्पादक संगठनों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (एफपीओ ट्रस्ट) और पशुपालन और डेयरी के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (एएचडी ट्रस्ट).

वित्त वर्ष 2024 में, कंपनी ने बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कई क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करके और ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं (ईएलआई) को शामिल करके योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे क्रेडिट गारंटी योजनाओं का कवरेज बढ़ गया.

भारत सरकार और नाबार्ड के निरंतर सहयोग से, 31 मार्च 2024 तक, 94 ईएलआई को एफपीओ न्यास के तहत पंजीकृत किया गया है और 55 ईएलआई को एएचडी न्यास के तहत पंजीकृत किया गया है.

31 मार्च 2024 तक, कुल 1,876 ऋण गारंटियां जारी की गई हैं, जिससे 23 राज्यों में 13.7 लाख किसानों वाले 1,479 एफपीओ द्वारा प्राप्त ₹401.4 करोड़ की कुल ऋण राशि के लिए ₹337 करोड़ का कवरेज मिला है, जिसके परिणामस्वरूप जारी की गई गारंटियों के मामले में 138% की वृद्धि हुई है. सभी नई ऋण गारंटियां, ऋण गारंटी पोर्टल के माध्यम से जारी की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्बाध प्रसंस्करण हुआ है, जिससे टर्नअराउंड समय कम हो गया है. एफपीओ न्यास के तहत क्रेडिट गारंटी योजना दिशानिर्देशों को अब एनबीएफसी (बीबीबी और उससे ऊपर) को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है.

एएचडी ट्रस्ट के तहत, पांच क्रेडिट गारंटियां जारी की गई हैं, जिसमें कुल ₹88.6 करोड़ का ऋण और ₹22.2 करोड़ का गारंटी कवर शामिल है. एएचडी ट्रस्ट के तहत ट्रैक्शन कम था क्योंकि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) केवल वित्त वर्ष 2023 तक ही लागू थी. हाल ही में, एएचआईडीएफ योजना को वित्तीय वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें डेयरी प्रसंस्करण आधारभूत संरचना विकास निधि भी शामिल कर ली गई है. संशोधित योजना के तहत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को शामिल करने के लिए ईएलआई का विस्तार किया गया है. ऋण गारंटी लाभ अब एमएसएमई के अलावा डेयरी सहकारी समितियों को भी दिया जाएगा.

नैबसंरक्षण को केरल जलवायु अनुकूलन कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत रबड़, कॉफी और इलायची बागानों के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, जिसमें नैबसंरक्षण ट्रस्टी और केरल सरकार सेटलर होगी. यह नैबसंरक्षण के प्रबंधन के तहत प्रथम राज्य ऋण गारंटी निधि होगी.

31 मार्च 2024 तक, कुल 1,876 ऋण गारंटियां जारी की गई हैं, जिससे 23 राज्यों में 13.7 लाख किसानों वाले 1,479 एफपीओ द्वारा प्राप्त ₹401.4 करोड़ की कुल ऋण राशि के लिए ₹337 करोड़ का कवरेज मिला है, जिसके परिणामस्वरूप जारी की गई गारंटियों के मामले में 138% की वृद्धि हुई है.

भारत सरकार ने मत्स्य आधारभूत संरचना विकास निधि को वित्तीय वर्ष 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की आधारभूत संरचना विकास निधि की वर्तमान ऋण गारंटी निधि से उद्यमियों, व्यक्तिगत किसानों और सहकारी समितियों की परियोजनाओं को भी नैबसंरक्षण के माध्यम से ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी.

नैबफाउंडेशन

विकास के उत्प्रेरक के रूप में नैबफाउंडेशन ने आजीविका सृजन, संधारणीय कृषि और ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, महिलाओं के प्रति जागरूकता, कौशल और क्षमता विकास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यटन, डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन आदि जैसे क्षेत्रों में कदम रखा. वर्ष के दौरान, नैबफाउंडेशन को नाबार्ड, नाबार्ड की सहायक कंपनियों और अन्य कॉर्पोरेटों से ₹18.3 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 31 परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिली.

कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं से 18 आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सहित 116 जिलों के 32 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), 80 उत्पादक कंपनियों, 35 कारीगरों और 500 से अधिक आदिवासी परिवारों सहित 1,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभ हुआ है.

वर्ष के दौरान आरंभ की गई नई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- **कृषि बाज़ार में ग्रामीण सशक्तीकरण के लिए डिजिटलीकरण**: इस परियोजना का उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और बिचौलियों के बीच मंडियों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है, ताकि व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित और परेशानी मुक्त बनाया जा सके. इससे इन हितधारकों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है.
- **क्लिक रामेश्वरम**: यह परियोजना पर्यटन के डिजिटल प्रचार के माध्यम से स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं की आजीविका में सुधार लाने का एक प्रयास है. इस परियोजना में क्षेत्र के 1,000 से अधिक पॉइंट्स ऑफ इंट्रेस्ट (दिलचस्प स्थानों) की जियोटैगिंग, क्यूआर कोड बनाना और उन्हें प्रमुख स्थानों पर रखना तथा विभिन्न वेबसाइटों पर होस्ट करने के लिए एक डिजिटल कॉफी टेबल बुक बनाना शामिल है.
- **पशु स्वास्थ्य देखभाल और चारे की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि**: इस परियोजना का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार के लिए पशु स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों और रोग की रोकथाम, पशुधन प्रबंधन आदि के बारे में स्थानीय समुदाय में जागरूकता पैदा करना है.
- **स्कूलों में शौचालयों का निर्माण**: वॉश पहल के एक हिस्से के रूप में, नैबफ़िन्स की सीएसआर निधि से जीएचपी स्कूल, बिरूर, चिकमगलूरु में एक शौचालय ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है. यह स्वच्छता सुविधा न केवल छात्रों और कर्मचारियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि छात्राओं की पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने में भी मदद करेगी.
- **उद्यमशीलता समर्थन के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाना**: इस परियोजना का उद्देश्य तमिलनाडु के तिरुप्पूर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है. परियोजना के एक हिस्से के रूप में, नैबवेंचर्स, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के एक समूह को मोबाइल बेकरी इकाई-सह-कैफेटेरिया शुरू करने में सहायता कर रहा है.
- **जिला परिषद स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना**: इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के पालघर में स्थित जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय में शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाना है, ताकि आदिवासी समुदाय की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. स्कूल में बिजली, स्वच्छ पेयजल, उचित स्वच्छता और डिजिटल शिक्षण संसाधनों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. नैबसंरक्षण की सीएसआर पहल के समर्थन से, परियोजना इन मुद्दों को संबोधित करेगी और गरीब आदिवासी परिवारों के 135 छात्रों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करेगी.
- **तमिलनाडु के धनुषकोडी में यात्री इको-सैनिटेशन और स्वच्छता**: नैबकिसन, नैबफिन्स और नैबफाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित यह परियोजना धनुषकोडी के इको-फ्रेजाइल क्षेत्र में स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय स्वच्छता सुविधाएँ बनाने का एक प्रयास है. इस परियोजना का उद्देश्य 'भुगतान और उपयोग' के आधार पर पोर्टेबल स्वच्छता के माध्यम से एसएचजी के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है. इस परियोजना में एक मोबाइल कैफेटेरिया भी शामिल है जो एसएचजी सदस्यों के लिए अतिरिक्त आय लाएगा.
- **सतही जल को बढ़ाने और जन संस्थाओं के माध्यम से जलवायु अनुकूलन बनाए रखने के लिए सिंचाई टैंकों को बहाल करना (रीएश्योर)**: इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक जल स्वामित्व को बढ़ावा देने, सिंचाई टैंक झरनों का पुनर्वास करने और जल उपयोगकर्ता संघों को बढ़ावा देकर टैंक आधारित आजीविका को मजबूत करने के लिए सामाजिक पूंजी का निर्माण करना है. इस परियोजना में पाँच सिंचाई टैंकों का जीर्णोद्धार भी शामिल है.
- **कुपोषण से बचाव**: इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके जशपुर में कुपोषण से लड़ना है. इस परियोजना में चिकित्सा स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर; कैल्शियम, विटामिन, आयरन और अन्य आवश्यक दवाओं का वितरण; किचन गार्डन को बढ़ावा देना; और पोषण से भरपूर फलों और सब्जियों के पौधों का वितरण शामिल है.
- **स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम**: भारत सरकार के इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत कम उम्र में ही कृषि के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करना है. इस परियोजना का लक्ष्य देश भर के 1,000 सरकारी स्कूलों में मिनी मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ स्थापित करना है.

कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं से 18 आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सहित 116 जिलों के 32 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), 80 उत्पादक कंपनियों, 35 कारीगरों और 500 से अधिक आदिवासी परिवारों सहित 1,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभ हुआ है.

छात्रों को निर्धारित मापदंडों पर मिट्टी की जाँच करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. किसान इन प्रयोगशालाओं में अपनी मिट्टी की जाँच भी करवा सकते हैं.

- **उज्ज्वल भविष्य की ओर**: इस परियोजना में इलाहाबाद के दो सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें शौचालयों का निर्माण, हाथ धोने का स्थान, कक्षाओं की मरम्मत, बिजली की फिटिंग, रसोई क्षेत्र, मध्याह्न भोजन कक्ष, कक्षाओं में वाटर कूलर, बेंच और पंखों आदि की आपूर्ति शामिल है. यह परियोजना पूरी तरह से इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके सीएसआर दायित्वों के तहत वित्तपोषित है.

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान आदिवासी गांवों में पेयजल आपूर्ति, दिव्यांग बच्चों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्कूल आधारभूत संरचना का विकास और 'मेरा पैड मेरा अधिकार' परियोजनाएं शुरू की गईं.

नोट्स

1. आईजीएएपी = सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत.
2. एनडबल्यूआर = परक्राम्य भंडारागार रसीदें.